# राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में भारत–अमेरिका संबंध का विश्लेषण

तेजप्रताप सिंह, शोधार्थी
डॉ अमरजीत कुमार सिंह
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
कन्या महाविद्यालय रीवा म0प्र0

संक्षेप
ओबामा के कार्यकाल में भारत अमेरिका के मध्य संबंधों में प्रगति हुई है। दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध पहले की तुलना में कई गुना बेहतर हुए हैं। राजनीतिक संबंधों में भी काफी सुधार हुआ है। और सामरिक संबंध सामरिक भागीदारी के स्तर पर पहुंच गए हैं बेहतर होते संबंध के कई कारणों में से एक भारत की आर्थिक क्षमता और दूसरा बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों एवं चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रमुख है। यद्यपि ओबामा के कार्यकाल के दौरान संबंधों के मध्य कुछ चुनौतियां भी मौजूद रहे लेकिन वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जिससे भारत अमेरिका संबंध विपरीत रूप से प्रभावित हो।
शब्दावली सामरिक संबंध ,द्विपक्षीय संबंध, प्रशासन

## परिचय

21वीं सदी की शुरुआत ने भारत अमेरिका संबंधों में नए अवसरों के युग की शुरुआत की। जबकि बीसवीं शताब्दी में द्विपक्षीय संबंध शीत युद्ध की राजनीति से प्रभावित थे, नई सदी में दोनों देशों के मध्य होते बेहतर संबंधों के प्रमुख कारण आर्थिक अवसर और चीन का उदय है। इस शोधपत्र में ओबामा प्रशासन के दौरान संबंधों का विश्लेषण किया गया है। भारत के उभरते हुए विशाल बाजार ने अमेरिका को भारत से संबंध बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। जबकि चीन के उदय ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंध के विस्तार को प्रोत्साहित किया । जिससे यह संबंध राजनीतिक और आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर सामरिक साझेदार के रूप में स्थापित हो गए हैं। इस अध्ययन को मुख्य रूप से दोनों देशों के मध्य राजनयिक, आर्थिक एवं सामरिक संबंध तक सीमित रखा गया है। राष्ट्रपति ओबामा और भारतीय प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के यहां यात्राएं की और द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई सारे समझौते किए। अमेरिका और भारत ने दक्षिण एशिया में शांति ,स्थायित्व और सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दिखाई।

## राजनीतिक संबंध

राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों में काफी प्रगति हुई थी लेकिन ओबामा ने राष्ट्रपति बनने पर प्रारंभ के 6 महीने भारत को महत्व नहीं दिया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड हालब्रूक ने तो कश्मीर मुद्दे को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात कही। अमेरिकी विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन ने जापान चीन दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया की यात्रा की लेकिन भारत नहीं आई । इससे भारत को यह संदेश गया
कि अमेरिका उसे उचित महत्व नहीं दे रहा है जैसा कि बुश प्रशासन के दौरान भारत को महत्व मिल रहा था । यद्यपि ओबामा के पहले कार्यकाल के दौरान प्रशासन को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जिससे निपटना ओबामा प्रशासन की पहली प्राथमिकता हो गई थी और विदेश नीति के क्षेत्र में ईरान इराक और अफगानिस्तान के मुद्दे को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया । भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण टोटके लेकिन उस समय भारत कोई बड़ा मुद्दा नहीं था।[1]
अमेरिका ने जल्द ही भारत को महत्व देना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत जुलाई 2009 में विदेश सचिव हिलेरी क्लिंटन की चार दिवसीय भारत यात्रा से हुई। क्लिंटन की इस यात्रा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया।[2] भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवंबर 2009 में वाशिंगटन की यात्रा की यह यात्रा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। पहला वाशिंगटन ने नई दिल्ली को तो यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अमेरिका के लिए कि विपक्षी संबंध और आतंकवाद की चुनौती तो वह महत्व देता है। ओबामा ने भारत को एशिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए यह घोषणा की कि एशिया में भारतीय नेतृत्व पूरे क्षेत्र में समृद्ध और सुरक्षा का विस्तार कर रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में भारत के नेतृत्व का स्वागत करता है और उसे प्रोत्साहित करता है।[3]
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा के 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति ओबामा ने भारत की यात्रा की । इस यात्रा के दौरान ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त ओबामा ने भारत को 21वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनिवार्य भागीदार कहा और यह आश्वासन दिया कि अमेरिका भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था वासेनार समूह ऑस्ट्रेलिया समूह और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता दिलवाने में मदद करेगा।[4]
सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की और न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हजारों भारती अमेरिकियों को संबोधित किया। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2005 के रक्षा सहयोग समझौते को और 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इस समझौते में कहा गया है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के साथ रक्षा के मुद्दों पर अपने निकटतम सहयोगी यों जैसा व्यवहार करेंगे इस शिखर सम्मेलन से भारत ने इस आशंका को दूर करने में मदद मिली कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विश्वसनीय भागीदार नहीं है और वह किसी विपरीत प्रभाव किसी विपरीत परिस्थिति में भारत को रक्षा सहयोग नहीं करेगा।[5]

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सम्मान मिला और ओबामा से पहले राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए 2 बार भारत की यात्रा पर आए। ओबामा ने भारत यात्रा को इतना महत्व दिया कि उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन के वार्षिक संबोधन को पुनर निर्धारित किया। गणतंत्र दिवस समारोह से 1 दिन पहले ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि शांति समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य निश्ड साझेदारी अनिवार्य है। इस संयुक्त बयान में भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति से बढ़कर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया।[6]

ओबामा प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के समक्ष कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियां बनी रही । न्यूयॉर्क में भारत के उप वाणिज्य महाद दूतावास में राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को एक घरेलू कामगार को अमेरिका ले जाने के लिए वीजा में की गई धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया इस प्रकरण ने भारत अमेरिका संबंधों के समस्त गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। दूसरा भारत की घरेलू राजनीति भी भारत अमेरिका संबंधों के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है भारत की वामपंथी पार्टियां अमेरिका को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और अमेरिका से किसी भी तरीके से बेहतर संबंध स्थापित करने के यह समर्थक नहीं है दूसरा भारतीय मुसलमान भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंधों के समर्थक नहीं है । इनके कारण विभिन्न रक्षा संबंधी परियोजनाओं को रोक दिया गया उदाहरण के लिए रक्षा मंत्री एके एंटनी के समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने 17 रक्षा संबंधित परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।[7]

अफगानिस्तान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और भारत किसी भी प्रकार का पाकिस्तानी प्रभाव अफगानिस्तान में नहीं चाहता इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में 2 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अफगानिस्तान से निकलने की मुद्दे पर भारत से परामर्श है भारत उसमें शामिल नहीं किया तीसरा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भारत और अमेरिकी रुख एक जैसे नहीं है यद्यपि भारत भी हमें ईरान के परमाणु हथियार हासिल

करने का समर्थक नहीं है लेकिन वह ईरान से परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य कार्यवाही का समर्थक नहीं है क्योंकि ईरान मध्य एशिया से भारत के संपर्क एवं भारत की ऊर्जा जरूरत है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारत ने अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक रेल और संपर्क सड़क संपर्क बनाने की योजना बना रखी है ताकि अफगानिस्तान से भारत में कच्चे माल और मध्य एशिया में माल को आसानी से पहुंचा जा सके भारत की मुस्लिम आबादी ईरान के साथ भारत के संबंध को बेहतर करना चाहती है और इसी कारण से वह अमेरिकी इरान में अमेरिकी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती यह कुछ भारत की भारत अमेरिका संबंधों राजनीतिक संबंधों के समक्ष गंभीर चुनौतियां।[8]

**आर्थिक संबंध**

बीसवीं शताब्दी में भारत और अमेरिका के मध्य अच्छे संबंधों के ना होने के पीछे एक कारण भारत की खराब आर्थिक स्थिति भी रहा है हालाकी बुश प्रशासन के दूसरे कार्यकाल द्विपक्षीय व्यापार बड़ा 2004 में 21 अरब अमेरिकी डालर से बढ़कर 2008 में 43 अरब अमेरिकी डालर हो गया ओबामा के दूसरे कार्यकाल के अंत तक व्यापार संबंध दोनों राज्यों के बीच तेजी से विस्तार हो रहा था। 2000 से 2017 में व्यापार में 600: से अधिक की वृद्धि हुई।[9]

संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 15 वर्षों में भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बन गया है। 2001 में भारत अमेरिका का 25 वा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और 2014 तक यह बढ़कर 11 वे स्थान पर पहुंच गया था जबकि अमेरिका 2001 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा का भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था यह 2014 में गिरकर पांचवा सबसे बड़ा हो गया कुल वृद्धि 2001 में 370 मिलियन से बढ़कर 2014 में 1.7 बिलियन हो गई सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सन 2000 के बाद अमेरिका से आने वाली एसबीआई में भी काफी वृद्धि हुई है वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान इसमें थोड़ी कमी आई है उसके अलावा अन्य वर्षो में विपक्षी एफडीआई में लगातार वृद्धि हुई है।[10]

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है लेकिन कई चुनौतियां भी रही हैं। ओबामा के शासनकाल में अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के बारे में अक्सर शिकायत की विशेष रुप से संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा और इस मुद्दे को देखने के लिए 2014 की मैं एक आउट ऑफ साइकिल समीक्षा ओ सी आर निर्धारित की। ओ सी आर बनाना एक वृद्ध थी क्योंकि इससे व्यापार प्रतिनिधि की रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसित प्रतिबंध लग सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट के नकारात्मक प्रभाव को महसूस करते हुए ओबामा और मोदी के बीच सितंबर 2014 के शिखर सम्मेलन में आईपीआर जैसे मुद्दों को निपटाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। इसके अलावा भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक थिंक टैंक की स्थापना की जो आईपीआर मुद्दों पर केंद्रित है।[11] 2012–13 के के दौरान अमेरिकी कंपनियों ने भारत पर संरक्षणवाद एवं भेदभाव पूर्ण कर लगाने का आरोप लगाया और अमेरिका ने इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन में उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय दवा उद्योग में उपयोग होने वाले कई संयंत्रों के भारतीय आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।[12]

**सामरिक संबंध**

ओबामा के कार्यकाल में भारत अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन दोनों देशों के मध्य रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए और इसका एक सबसे बड़ा कारण चीन के उदय को माना जाता है। चीन को नियंत्रित दोनों देशों के साझा उद्देश्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सुरक्षा क्षेत्र में भारत के साथ काम करने से अमेरिकी आज पति को बनाए रखने में मदद मिलती है जबकि चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंदिता में भी सहायता करता है। 29 राज्य राज्यों का यह प्रयास है कि वह चीन को नियंत्रित रखें। भारत आर्थिक क्षेत्र में चीन के साथ आर्थिक सहयोग कर रहा है लेकिन साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए सामरिक क्षेत्र में उसे नियंत्रित करने के लिए

अमेरिका के साथ सहयोग कर रहा है। अमेरिका की दृष्टि में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए अमेरिका भारत के साथ अत्यधिक सामरिक सहयोग कर रहा है यहां तक कि उसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार मान रहा है।

2009 से 2017 के बीच अमेरिकी ने भारतीय सेना को उन्नत हथियार प्रणाली प्रदान की। इन हथियारों में सी 130 जे एस सुपर हरक्यूलिस, 10 सी–17 परिवहन विमान, 24 हार्पून ब्लॉक मिसाइलें, 8 पनडुब्बी रोधी हथियार, अपाचे हेलीकॉप्टर आदि शामिल है। भारत और अमेरिकी सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। सामरिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग से भारत को अमेरिकी तकनीक और जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही मालाबार जैसे सैन्य अभ्यासों से अपनी रणनीति में सुधार करने में सक्षम हुआ है। चीन की भारत को घेरने की रणनीति के मद्देनजर अमेरिका के साथ भारत का सैन्य सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है।[13]

## निष्कर्ष

ओबामा के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध काफी ऊंचाइयों तक गए। यद्यपि शुरुआती 6 महीने अमेरिकी प्रशासन का ध्यान भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की बजाय वित्तीय संकट से निपटना अफगानिस्तान और इराक से सेना को वापस बुलाने संबंधी मुद्दे और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा लेकिन जुलाई 2009 में हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा और उसके पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नवंबर में वाशिंगटन की यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों में गर्माहट पुणे पैदा कर दी। जैसे–जैसे द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि हुई तो उन चुनौतियों को जो दोनों देशों के मध्य आ रही थी उनसे भी निपटने का प्रयास किया गया बौद्धिक संपदा अधिकार और बाजार पहुंच पर दोनों देश पर चिंताएं रिश्ते में प्रमुख बाधाएं बन गई थी। ओबामा की कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यद्यपि जितनी क्षमता थी इतनी वृद्धि नहीं हुई। इस इस काल में दोनों देशों के मध्य सबसे ज्यादा सुधार सामरिक संबंधों में हुआ। उभरते हुए चीन का सामना करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साझे सामरिक हित थे।

सन्दर्भ–

1. एन, बर्न्स, पैसेज टू इंडिया, फॉरेन अफेयर्स, 2014, पृ134
2. सी महापात्रा, ओबामा एडमिनिस्ट्रेषन।। एंड इंडिया इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल 8:2,2013, पृ 196
3. ब्हाइट हाउस रिमार्क बाई प्रसिडेन्ट ओबामा एंड प्राइमिनिस्ट्रर सिंह ऑफ इडिया इन ज्वाइन्ट प्रेस कॉनफ्रेन्स।
4. महापात्रा, ओबामा प्रषासन।। और भारत पृ,194
5. जी. तेजा, द न्यू इंडिया– यू एस रिसेट, अमेरिकन फारेन पॉलिसी इंटरेस्ट, 36:6,2014 पृ 382
6. वाइट, हाउस एषिया प्रषांत ओर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए अमेरिका भारत संयुक्त रणनीतिक दृष्टि, 25 जनवरी 2015
7. ए, वासुदेव, यूएस इंडिया डिफेंस टाईजः ए डेलिकेट डांस, फॉरेन पॉलिसी, 8 अक्टूबर 2015
8. जेडी स्मिथ, द एषिया पेसिफिक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल इंटेंस लाइन इडिया चाइना यूएस रिलेषंन ऑन कनफ्लिक्ट्स एंड इन साउथ एषिया जर्नल ऑफ एषियन सिक्योरिटी एंड इंटरनेषनल अफेयर्स, 1:2 , 2014 पृ 2014–16
9. यू0एस0 सेंसस ब्यूरो, ट्रेड इन गुड्स विद इंडिया, 10 मार्च 2019
10. डेलिस और मोहन, स्ट्रैटेजिक रिलेषन, पृ 16
11. ब्रुकिंग्स इंडिया सेंटर, द सेकंड मोदी–ओबामा समीट, पृष्ठ 27
12. डेलिस एंड मोहन, द स्ट्रैटिजिक रिलेषन, पृ 31–32
13. गांगुली, सी के, 2020, ओबामा एडमिनिस्ट्रेषन एंड इंडिया, इन परमार, द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडो–पेसिफिक ओबामास लीगेसी एंड द ट्रंप ट्रांजिषन, पृष्ठ 362, मैनचेस्टर यूनिवसिटी प्रेस